वित्त विधेयक, 1974 में आयकर के लिए छूट की सीमा बढ़ाने के लिए हाल में किया गया प्रस्ताव और करों के दर के ढांचे में किया गया नया संशोधनों, जिससे कर में राहत मिली है, इसी प्रकार का उपाय है। इसके अतिरिक्त अन्य राज्य सम्बन्धी और वित्तीय उपाय भी चल रहे है। जिनमें अन्य उपायों के साथ ये उपाय शामिल है जैसे भविष्य निधियों और बीमा पालिसियों के माध्यम से की जाने वाली स्वीकृत बचतों को एक निर्धारित सीमा तक आयकर से मुक्त रखना, भविष्य निधियों में एकत्रित रकमों के ब्याज को बढ़ाना और ग्रेच्युटी तथा पेंशन के लाभों के सम्बन्ध में अधिक उदारता बरतना आदि।

मारुति के डायरेक्टरों को जारी किये गये आयात लाइसेंस

8337. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति लिमिटेड के उन डायरेक्टरों, उच्चतम अधिकारियों तथा 1000 रुपये अथवा इससे अधिक के अंशधारियों के नाम क्या है, और

(ख) गत तीन वर्षों में उनमें से प्रत्येक को दिये गये आयात लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) मैसर्स मारुति लिमिटेड में अंशपूंजी के रूप में 1000 रु० अथवा उससे अधिक के अंशधारियों तथा डायरेक्टरों के नामों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी। सरकार को मैसर्स मारुति लिमिटेड के उच्च अधिकारियों के नामों की जानकारी नहीं है।

(ख) आयात लाइसेंसों के ब्यौरे, आयात निर्यात के मुख्य नियन्त्रक द्वारा जारी की जाने वाली वीकली बुलिटिन्स आफ इंडस्ट्रीयल लाइसेंसिस, इंपोर्ट लाइसेंसिस एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसिस में प्रकाशित किए जाते है जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

Representation received from small farmers and traders regarding credit squeeze policy of RBI

8338. SHRI N SHIVAPPA Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) whether he had received representations from the small farmers and traders regarding RBI credit squeeze policy; and

(b) if so, whether any enquiry has been conducted into their grievances?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): (a) and (b). While the main stress in the Reserve Bank's current credit policy is on overall restraint on credit creation, the Reserve Bank has at the same time emphasized to the banks the need for giving due importance to priority sector lending including lending to such categories as farmers and small traders. Despite this emphasis, there have been occasional references from various quarters pointing out that certain aspects of the credit policy such as increased margins, increased interest rates etc. create problems. Matters of this type are under continuous study of the Reserve Bank for devising such remdial actions as might be considered necessary.